

ब्यूज टुडे

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 1 अरब से अधिक लोग मानसिक स्वास्थ्य विकारों से ग्रसित हैं

WHO ने 'वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे' और 'मेंटल हेल्थ एटलस 2024' शीर्षक से दो नवीनतम रिपोर्ट्स जारी की हैं। इनमें वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के व्यापक प्रसार को उजागर किया गया है। इससे एक अरब से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं और साथ ही, इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा बोझ पड़ता है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- ▶ बढ़ता प्रसार: आंकड़ों के अनुसार, 2021 में वैश्विक जनसंख्या का 14% हिस्सा मानसिक विकार से पीड़ित था।
- ▶ सबसे आम विकार: सभी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के दो-तिहाई से अधिक के लिए एंग्जायटी और अवसाद जैसे विकार जिम्मेदार हैं।
- ▶ लैंगिक असमानताएं: महिलाएं एंग्जायटी, अवसाद और ईटिंग डिसऑर्डर से अधिक ग्रस्त हैं।
- ▶ युवाओं पर प्रभाव: लगभग आधे मानसिक विकार 18 वर्ष की आयु से पहले ही शुरू हो जाते हैं।
- ▶ मानसिक स्वास्थ्य प्रणालियों की अत्यधिक कमी: इसके लिए निम्नलिखित कारक जिम्मेदार हैं:
 - ⊕ अपर्याप्त निवेश जैसे सरकारें औसतन अपने स्वास्थ्य बजट का केवल 2% हिस्सा ही मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च करती हैं,
 - ⊕ मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भारी कमी,
 - ⊕ उपचार की सीमित उपलब्धता, आदि।

मानसिक विकारों के परिणाम

- ▶ आत्महत्या: 2021 में, 15-29 वर्ष की महिलाओं में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण आत्महत्या था। इसी आयु वर्ग के पुरुषों में मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण आत्महत्या था।
- ▶ अनौपचारिक देखभाल का बोझ: अनौपचारिक देखभाल के तहत मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकारों के उपचार पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। इसकी वजह से परिवार के सदस्यों और अन्य अनौपचारिक देखभालकर्ताओं पर अत्यधिक सामाजिक, आर्थिक एवं भावनात्मक बोझ पड़ता है।
- ▶ आर्थिक परिणाम: कई देशों में मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का आर्थिक बोझ सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% - 1.0% के बीच तक है।

मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें

▶ भारत में:

- ⊕ राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग (टेली-मानस)।
- ⊕ मनोदुर्घटना: इसके तहत कोविड-19 के दौरान और उसके बाद भी छात्रों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान की जाती है।
- ⊕ राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम: इसका उद्देश्य सभी के लिए एक निश्चित स्तर की मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करना है।

▶ वैश्विक स्तर पर:

- ⊕ पारो डिक्लेरेशन: इसका उद्देश्य जन-केन्द्रित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है।
- ⊕ मानसिक, तलिका संबंधी और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बढ़ाने हेतु WHO द्वारा मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम चलाया जा रहा है।

APEDA ने कृषि-खाद्य स्टार्ट-अप को समर्थन देने और भारत के कृषि-खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारती (BHARATI) नामक पहल शुरू की

यह पहल सरकार के आत्मनिर्भर भारत और स्टार्ट-अप इंडिया विज़न से जुड़ी हुई है। यह भारत की वैश्विक कृषि-खाद्य व्यापार में भागीदारी को मजबूत करेगी।

BHARATI के बारे में

- ▶ BHARATI का अर्थ है- भारत हब फॉर एग्रीटेक, रेज़िलियंस, एडवांसमेंट एंड इन्क्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनेबलमेंट।
- ▶ मुख्य उद्देश्य:
 - ⊕ इसका उद्देश्य 100 कृषि-खाद्य स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना और 2030 तक 50 बिलियन डॉलर का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करना है।
 - ◆ चुने गए स्टार्ट-अप 3 महीने के विशेष कार्यक्रम से गुजरेंगे, जिसमें उत्पाद विकास, निर्यात की तैयारी, विनियमों का पालन, और बाजार तक पहुंच जैसे प्रशिक्षण शामिल होंगे।
 - ⊕ ऐसे स्टार्ट-अप को आकर्षित करना, जो उन्नत तकनीकों पर काम कर रहे हों: जैसे- AI आधारित गुणवत्ता नियंत्रण, ब्लॉकचेन से जुड़ी ट्रेसिबिलिटी (उत्पाद की पूरी जानकारी ट्रैक करना), IoT आधारित कोल्ड चेन, एग्री-फिनटेक, आदि।
 - ⊕ उच्च-मूल्य श्रेणियों में नवाचार को बढ़ावा देना: जैसे- GI टैग किए गए कृषि उत्पाद, ऑर्गेनिक फूड्स, सुपरफूड्स, नए तरह के प्रोसेस्ड भारतीय कृषि-खाद्य उत्पाद, पशुपालन से जुड़े उत्पाद, आयुष उत्पाद, आदि।
 - ⊕ निर्यात से जुड़ी चुनौतियों का समाधान निकालना: जैसे- उत्पाद विकास, मूल्य संवर्धन, गुणवत्ता आश्वासन, जल्दी खराब होने वाले उत्पादों की समस्या, बर्बादी और लॉजिस्टिक्स से जुड़े मुद्दे, आदि।

कृषि-स्टार्ट-अप की कृषि-निर्यात बढ़ाने में भूमिका

- ▶ आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करना: फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मांग-आधारित कोल्ड चेन, गोदाम की निगरानी और बाजार से जुड़ाव को मजबूत करते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखना भी आसान होता है।
 - ▶ गुणवत्ता में सुधार: किसानों को बेहतर बीज, खाद एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ताकि उनकी पैदावार ज्यादा हो और उत्पाद निर्यात के योग्य बन सके।
 - ▶ प्रोसेसिंग और ट्रेसिबिलिटी (उत्पाद की ट्रैकिंग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को संगठित करते हैं तथा उत्पाद की पूरी जानकारी (ट्रेसिबिलिटी) उपलब्ध कराते हैं। इससे किसानों की आमदनी बढ़ती है और निर्यात प्रतिस्पर्धा भी मजबूत होती है।
 - ▶ तकनीक का इस्तेमाल: बिग डेटा व IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) का उपयोग कर परिशुद्ध कृषि व कीट नियंत्रण में सहायता करते हैं और मौसम का पूर्वानुमान भी प्रदान करते हैं, ताकि हमेशा उच्च गुणवत्ता वाली फसल तैयार हो सके जो निर्यात योग्य हो।
 - ▶ बाजार से जुड़ाव: बाजार से जुड़ने के नए मॉडल तैयार करते हैं, जो फसल उत्पादन को उपभोक्ता की मांग से सीधा जोड़ सके। इससे सही समय पर और प्रभावी ढंग से निर्यात ऑर्डर पूरे किए जा सकते हैं।
- कृषि स्टार्ट-अप भारत की खेती को जीविका आधारित खेती से मुनाफ़ा कमाने वाले उद्यम में बदलने में अहम भूमिका निभा रहे हैं और इससे कृषि-निर्यात पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है।

भारत का पहला 32-बिट प्रोसेसर 'विक्रम3201' सेमीकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री के समक्ष पेश किया गया

देश का लक्ष्य वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल करना है। इस उद्योग के 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यह विकास नीतिगत अनुमोदन से लेकर प्रारंभिक उत्पादन तक के सफल बदलाव को दर्शाता है।

सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) और SEMI ने संयुक्त रूप से किया है। सेमीकॉन इंडिया 2025 एक प्रमुख मंच है, जो भारत में सेमीकंडक्टर्स के भविष्य को आकार देने के लिए वैश्विक नेताओं, नवप्रवर्तकों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को एक साथ लाता है।

विक्रम3201 प्रोसेसर के बारे में

- यह स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए 16-बिट विक्रम1601 माइक्रोप्रोसेसर का एक उन्नत संस्करण है। 16-बिट विक्रम1601 माइक्रोप्रोसेसर का 2009 से इसरो के प्रक्षेपण यानों के एवियोनिक्स सिस्टम में उपयोग किया जा रहा है।
- यह पूरी तरह से "मेक-इन-इंडिया" 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर है। इसे प्रक्षेपण यानों की कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए अनुकूल बनाया गया है।
- विकासकर्ता: ISRO के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) ने चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी (SCL) के सहयोग से इसका डिजाइन व विकास किया है।
- आर्किटेक्चर: इसमें एक कस्टम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, जो फ्लोटिंग-पॉइंट गणना करने में सक्षम है।

भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए सरकारी पहलें

- इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM): इसे 2021 में अनुमोदित किया गया था। यह भारत में एक संधारणीय और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले मैनुफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करने के लिए नोडल एजेंसी है।
- संशोधित डिजाइन-से संबद्ध प्रोत्साहन (DLI) योजना: इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर विनिर्माण में भारतीय बौद्धिक संपदा का निर्माण करना है।

ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों को निशाना बनाते हुए आग्रजन (Immigration) विरोधी प्रदर्शन किए गए

इस विरोध प्रदर्शन को "मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया" नाम दिया गया है। इस प्रदर्शन की ऑस्ट्रेलियाई संसद के सदस्यों ने निंदा की है। यह विरोध प्रदर्शन ग्लोबल नॉर्थ में बढ़ती आग्रजन विरोधी भावना को दर्शाता है।

- यूनाइटेड किंगडम के बाद भारतीय प्रवासियों की दूसरी सर्वाधिक संख्या ऑस्ट्रेलिया में है। जून 2023 तक, लगभग 8,40,000 भारतीय मूल के निवासी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे।

ग्लोबल नॉर्थ में आग्रजन विरोधी भावना के लिए जिम्मेदार कारक

- सुरक्षा संबंधी कारक: प्रवासन को राष्ट्रीय और सांस्कृतिक सुरक्षा के समक्ष खतरे के रूप में देखा जा रहा है। इस कारण देशों में प्रवासियों के प्रवेश से संबंधित कठोर नियम बनाए जा रहे हैं। कई लोगों के अनुसार बड़ी संख्या में प्रवासियों के कारण उन्हें अपने ही देशों में "घर जैसा महसूस" नहीं होता। उदाहरण के लिए- ब्रेकिंग अभियान।
- आर्थिक संरक्षणवाद: प्रवासियों से संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। इसका भी भय रहता है कि प्रवासी कम वेतन पर काम करके स्थानीय कामगारों से रोजगार छीन सकते हैं। इससे स्थानीय नागरिक बेरोजगार हो जाएंगे।
- राष्ट्रवाद और डी-ग्लोबलाइजेशन: बढ़ता राष्ट्रवाद और वैश्विक जुड़ाव से पीछे हटना, प्रवासियों के कल्याण की तुलना में घरेलू हितों को प्राथमिकता देते हैं।
 - दक्षिणपंथी लोकलुभावनवाद: ऐसे राजनीतिक दल प्रवासी विरोधी भावना को हथियार बनाते हैं तथा प्रवासियों को स्थानीय पहचान और सुरक्षा के समक्ष प्रत्यक्ष खतरे के रूप में चित्रित करने जैसे भ्रामक विचारों का प्रसार करते हैं।
- विदेशियों के प्रति घृणा (जेनोफोबिया) और सांस्कृतिक हिंसा: "अदरनेस" और राष्ट्रीय पहचान की सुरक्षा के डर को बढ़ा देने वाले मीडिया प्रचार तथा राजनीतिक बयानबाजी प्रवासियों के प्रति नकारात्मकता को बढ़ाते हैं।

भारत के लिए प्रवासी समुदाय का महत्व

- विप्रेषण (Remittance): भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा विप्रेषण प्राप्त करने वाला देश है। 2023-24 में 118.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विप्रेषण प्राप्त हुआ था।
- राजनीतिक: ये कूटनीति और लॉबीइंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं (जैसे भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता)।
- सॉफ्ट डिप्लोमेसी: ये भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य, त्यौहार, व्यंजन, भारतीय फिल्मों, योग, आदि के माध्यम से सॉफ्ट डिप्लोमेसी को बढ़ावा देते हैं।

प्रवासी भारतीयों के लिए शुरु की गई पहलें

- भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF): इसका उद्देश्य संकट के समय प्रवासी भारतीय नागरिकों की सहायता करना है।
- प्रवासी भारतीय बीमा योजना (PBBY): इसे आकस्मिक मृत्यु के मामले में 10 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करने के लिए 2017 में शुरू किया गया था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सशक्त महिलाएं विकसित भारत की मजबूत नींव हैं

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने 'बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड' पहल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के वित्तीय समावेशन के महत्त्व पर प्रकाश डाला।

पहल के बारे में

- उद्देश्य: जीविका (Jeevika) सदस्यों के लिए आसान और वहनीय ब्याज दरों पर डिजिटल तरीके से फंड उपलब्ध कराना। इस प्रकार, बिहार की ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना।
 - जीविका: यह बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना (BRLP) है, जिसका लक्ष्य गरीबी कम करना है। यह योजना SHGs को समर्थन देकर ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देती है।
 - इसका उद्देश्य उच्च ब्याज दर वसूलने वाली सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFI) पर निर्भरता को कम करना है।

महिला सशक्तिकरण में SHGs की भूमिका

- आर्थिक सशक्तिकरण: SHGs महिलाओं को औपचारिक ऋण, रोजगार और आय प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। इससे महिलाएं अपने परिवार के फैसलों में भागीदारी कर पाती हैं। उदाहरण: SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम।
- सामाजिक सशक्तिकरण: SHGs में महिलाओं का सामूहिक जुड़ाव आत्मविश्वास और सामाजिक सहयोग बढ़ाता है। इससे महिलाएं समाज में फैली लैंगिक असमानता और भेदभाव से लड़ पाती हैं। SHGs स्वास्थ्य सेवा और बाल विकास में महिलाओं को लाभान्वित करते हैं। उदाहरण के लिए- केरल में कुदुम्बश्री।
- राजनीतिक सशक्तिकरण: SHGs महिलाओं को अपने अधिकारों और हितों की वकालत करने तथा जमीनी स्तर पर नीतियों के कार्यान्वयन में भाग लेने में सक्षम बनाते हैं। ये उन्हें राजनीतिक नेतृत्व और निर्णयकारी भूमिकाओं में भी सशक्त बनाते हैं।

चुनौतियां: सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण उद्यमों का विस्तार मुश्किल हो जाता है; परिवार और समुदाय में पिछड़े दृष्टिकोण (जैसे परिवार की ओर से विरोध); प्रमुख समूहों का एकाधिकार जिससे समान लाभ पाने में बाधा आती है, आदि।

महिला सशक्तिकरण के लिए SHGs के माध्यम से प्रमुख पहलें

- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) और लखपति दीदी पहल: 3 करोड़ लखपति दीदियों (वह SHG सदस्य, जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये या उससे अधिक है) को सक्षम बनाना।
- महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म: नीति आयोग का एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, जो महिला उद्यमियों को संबंधित जानकारी और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है।
- स्टैंड-अप इंडिया और मुद्रा योजना/ महिला उद्यमि योजना: महिलाओं के लिए वित्तीय और उद्यमिता समर्थन।
- संचार शक्ति पहल: महिला SHGs को ICT-सक्षम सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके सशक्त बनाना।

सरकार ने एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 के दौरान गन्ने के रस और शीरे से एथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी

▶ एथेनॉल उत्पादन में चीनी का उपयोग करने के फैसले की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। इससे साल भर चीनी की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

- ⊕ राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में एथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल की एक विस्तृत सूची दी गई है। इसमें गन्ने का रस, चुकंदर, मीठा ज्वार, मक्का, कसावा, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न (गेहूँ व टूटा चावल), और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त सड़े हुए आलू शामिल हैं।

जैव ईंधन क्या है?

- ▶ जैव-ईंधन ऐसे तरल या गैसीय ईंधन हैं, जो मुख्य रूप से बायोमास (नवीकरणीय संसाधन) से तैयार किए जाते हैं।
- ▶ इनका उपयोग परिवहन, पोटेंबल एवं अन्य कार्यों के लिए डीजल, पेट्रोल या अन्य जीवाश्म ईंधन की जगह पर या उनके साथ मिश्रण में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए- एथेनॉल, कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) आदि।
- ▶ पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।
 - ⊕ भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

जैव ईंधन के लाभ

- ▶ स्वच्छ पर्यावरण: 1 करोड़ लीटर E-10 (10% एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल) से लगभग 20,000 टन CO₂ उत्सर्जन की बचत होती है।
- ▶ आयात में कमी: पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से पिछले 10 वर्षों में 1.10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।



जैव ईंधन की पीढियां

पीढियां	स्रोत	लाभ
प्रथम	खाद्य फीडस्टॉक (जैसे गेहूँ, मक्का, गन्ना आदि), खाद्य-ग्रेड रेपसीड, सोयाबीन या पाम ऑयल	लागत कुशल, सरल प्रक्रियाएं और अधिक पूर्व-उपचार की आवश्यकता नहीं।
दूसरी	लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और अपशिष्ट (जैसे गेहूँ की भूसी, पशु वसा, खाना पकाने और तलने के तेल का अपशिष्ट, जैट्रोफा कर्म्स, आदि)	चक्रीय अर्थव्यवस्था (अपशिष्ट का उपयोग), भोजन बनाम ईंधन के संघर्ष को समाप्त करता है।
तीसरी	सूक्ष्म शैवाल और सायनोबैक्टीरिया बायोमास	CO ₂ का सीधा अभिग्रहण (Capture), कोई भूमि उपयोग परिवर्तन नहीं और ताजे जल का कम उपयोग आदि।
चौथी	आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड सूक्ष्मजीव। उदाहरण के लिए- एस्चेरिचिया कोलाई और सैक्रोमाइसेस सेरेविसी	उच्च पैदावार, CO ₂ का सीधा उपयोग आदि।

सुर्खियां

विश्व व्यापार संगठन-सुरक्षा उपायों पर समिति

भारत ने तांबा के कुछ उत्पादों पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शिकायत दर्ज कराई है। भारत के अनुसार, अमेरिका का यह कदम 'सुरक्षात्मक उपाय' (Safeguard measures) है और WTO के नियमों के तहत इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई।

▶ इस कदम से प्रभावित देश होने के नाते भारत ने अमेरिका से परामर्श की मांग की है।

‘विश्व व्यापार संगठन-सुरक्षा उपायों पर समिति’ के बारे में

▶ यह समिति विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को 'सुरक्षात्मक उपायों' से संबंधित समझौते के संचालन से जुड़े किसी भी मामले पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है।

- ⊕ सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित समझौते में 'सुरक्षात्मक उपायों' के उपयोग के संबंध में नियम निर्धारित किए गए हैं।

- ⊕ 'सुरक्षात्मक उपाय' उन कुछ उत्पादों के बढ़ते आयात को देखते हुए "आपातकालीन" कार्रवाई के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जिनसे आयातक देश के घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है।

▶ कार्य:

- ⊕ यह समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करती है और इससे संबंधित रिपोर्ट 'वस्तु व्यापार परिषद' (CTG) को प्रस्तुत करती है।
- ⊕ सदस्य देशों के अनुरोध पर, यह समिति प्रक्रिया संबंधी अनुपालन का आकलन करती है और अपने निष्कर्षों को रिपोर्ट करती है।

आप्रवास और विदेशी विषयक (उन्मुक्ति) आदेश, 2025

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आप्रवास और विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 के तहत आप्रवास और विदेशी विषयक आदेश, 2025 को अधिसूचित किया।

आदेश के मुख्य प्रावधान

▶ निम्नलिखित को पासपोर्ट/वीजा से उन्मुक्ति प्रदान की गई है:

- ⊕ ड्यूटी पर तैनात भारतीय सशस्त्र बल को;
- ⊕ निर्धारित सीमाओं पर भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिक को;
- ⊕ वैध पंजीकरण और विशेष परमिट वाले तिब्बतियों को;
- ⊕ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर, 2024 तक भारत में आए निर्धारित धार्मिक अल्पसंख्यक (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई), भले ही उनके पास वैध दस्तावेज़ न हों;
- ⊕ पंजीकृत श्रीलंकाई तमिल नागरिक जिन्होंने 9 जनवरी, 2015 तक भारत में शरण ली थी।

▶ वीजा संबंधी उन्मुक्ति निम्नलिखित पर भी लागू होती है:

- ⊕ राजनयिक/आधिकारिक पासपोर्ट रखने वाले विदेशियों पर (जहां समझौते के तहत छूट दी गई हो);
- ⊕ वीजा-ऑन-अराइवल के लिए पात्र विदेशियों पर;
- ⊕ नौसेना के युद्धपोत पर आने वाले कुछ विदेशी सैन्य कर्मियों पर।



परिहार (Remission)

सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है कि आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्तियों को परिहार का संवैधानिक और वैधानिक अधिकार प्राप्त है।

परिहार (Remission) के बारे में

- परिभाषा: इसका अर्थ है सजा के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी सजा की अवधि कम करना।
- अनुच्छेद 72: भारतीय संविधान राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने तथा दंड को निलंबन या लघुकरण करने की शक्ति प्रदान करता है।
 - अनुच्छेद 161: राज्यपाल को भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति के दायरे में किसी भी कानून के विरुद्ध ऐसे किसी भी अपराध के लिए राष्ट्रपति के समान क्षमादान शक्तियां प्रदान करता है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 477: यह केंद्र सरकार के कानूनों के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की सजा के परिहार या उसे कम करने (लघुकरण) की राज्य सरकार की शक्ति से संबंधित है।



नारियल विकास बोर्ड

नारियल विकास बोर्ड ने संशोधित योजनाएं लॉन्च की है।

नारियल विकास बोर्ड के बारे में

- परिचय: यह केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक सांविधिक संस्था है।
- स्थापना: 1981 में
- उद्देश्य: नारियल की खेती और उद्योग का एकीकृत विकास करते हुए उत्पादकता में वृद्धि और उत्पाद विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करना।
- कार्यालय: मुख्यालय कोच्चि में है तथा क्षेत्रीय-कार्यालय बंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी और पटना में स्थित हैं।
- कार्य: नारियल उद्योग के विकास के लिए उपाय अपनाना, तकनीकी परामर्श देना, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, आदि।



पावर ऑफ साइबेरिया-2 पाइपलाइन

रूस और चीन ने पावर ऑफ साइबेरिया-2 (PoS 2) गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए।

पावर ऑफ साइबेरिया-2 पाइपलाइन के बारे में

- यह रूस के पश्चिमी साइबेरिया में स्थित गैस भंडार से गैस को पूर्वी मंगोलिया से होते हुए उत्तरी चीन तक आपूर्ति करेगा।
- इसका उद्देश्य पूर्वी साइबेरिया से चीन तक जाने वाली मौजूदा 'पावर ऑफ साइबेरिया' पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को बढ़ाना है।
- इसे पहले अल्ताई पाइपलाइन के नाम से जाना जाता था।



UNCTAD द्वारा ग्लोबल ट्रेड अपडेट जारी

UNCTAD के ग्लोबल ट्रेड अपडेट के अनुसार व्यापार नीति से संबंधित अनिश्चितता (वर्ल्ड पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स) वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में एक बड़ी बाधा के रूप में उभर रही है।

'ग्लोबल ट्रेड अपडेट' के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- व्यापार नीति संबंधी अनिश्चितता अभूतपूर्व स्तर पर है तथा यह टैरिफ की तुलना में भी अधिक बाधक है।
- नीतिगत अनिश्चितता के कारण लागत बढ़ जाती है, विकास की गति धीमी हो जाती है और वित्तीय अस्थिरता बढ़ती है।
- नीतिगत अनिश्चितता से लघु कंपनियों और अल्पविकसित देशों (LDCs) को अधिक खतरा है।
- सरकारें नीतिगत अनिश्चितता का उपयोग लाभ कमाने की मंशा के साथ-साथ रणनीतिक साधन के रूप में करती हैं।
- बाजारों में विविधता लाने और व्यापार समझौतों में शामिल होने से अनिश्चितता के खतरों से बचने में मदद मिलती है।



"सोलो पैराडॉक्स"

- "सोलो पैराडॉक्स" की अवधारणा नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट सोलो ने 1987 में दी थी। यह उस स्थिति का वर्णन करती है जिसमें कंप्यूटर जैसी अत्याधुनिक तकनीक के व्यापक उपयोग के बावजूद उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि नहीं होती।
- सोलो ने कहा था, "आप कंप्यूटर युग को हर जगह देख सकते हैं, लेकिन उत्पादकता के आंकड़ों में नहीं।"
- हालांकि, 1990 के दशक में इस मूल पैराडॉक्स का समाधान हो गया, जब बैंकिंग और रिटेल जैसे उद्योगों ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और प्रक्रिया री-डिजाइन से उत्पादकता में वृद्धि प्रदर्शित की।
- वर्तमान में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने के साथ भी इसी प्रकार का विरोधाभास सामने आ रहा है, क्योंकि कई संगठन अभी भी अपने मूल्य में अपेक्षित वृद्धि दर्ज नहीं कर पा रहे हैं।



मैत्री अभ्यास

मैत्री अभ्यास का 14वां संस्करण मेघालय (भारत) में शुरू हुआ।

मैत्री अभ्यास के बारे में

- इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। यह भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित महत्वपूर्ण संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यासों में से एक है।
- यह संयुक्त अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कंपनी स्तर पर आतंकवाद-रोधी अभियानों पर केंद्रित रहेगा।

सुर्खियों में रहे स्थल



सेशेल्स (राजधानी: विकटोरिया)

भारतीय नौसेना के फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में लॉन्ग रेंज प्रशिक्षण तैनाती के तहत सेशेल्स के पोर्ट विकटोरिया पहुंचा।

भौगोलिक अवस्थिति

- सेशेल्स पश्चिमी हिंद महासागर में मेडागास्कर के उत्तर-पूर्व में स्थित है। यह 155 द्वीपों वाला द्वीपसमूह है।
- यह क्षेत्रफल और जनसंख्या, दोनों दृष्टियों से सबसे छोटा अफ्रीकी देश है।

भौगोलिक विशेषताएं

- यह द्वीप-समूह 'मस्करेन' नामक समुद्री (सबमरीन) पठार के ऊपर स्थित है।
- इस द्वीप-समूह में 42 ग्रेनाइटिक और 113 कोरालाइन द्वीप शामिल हैं। इसका सबसे बड़ा द्वीप माहे है।
- यह पांच द्वीप-समूहों में विभाजित है: अमीरांतेस समूह, दक्षिणी कोरल समूह, अल्फोंस समूह, फर्क़ार समूह और एल्डब्रा समूह।
- स्थलाकृति: माहे समूह ज्वालामुखी है, जिसकी तटरेखाएं संकरी और आंतरिक भाग पहाड़ी है; शेष अधिकतर भाग समतल कोरल एटॉल्स या ऊंची रीफ्स हैं।



अहमदाबाद



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



जयपुर



जोधपुर



गुवाहाटी



हैदराबाद



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची



सीकर